16 स्कूली अर्थशास्त्र की दुविधा और चुनौती

अरविन्द सरदाना



इस पर अभी भी विवाद है कि स्कूली स्तर पर अर्थशास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। अनेक लोगों को लगता है कि गणित, इतिहास या भूगोल के समान एक विशेष विषय की तरह अर्थशास्त्र पाठ्यचर्या में स्थान पाने की पात्रता नहीं रखता। स्कूली पाठ्यचर्या को बुनियादी योग्यताओं और कौशलों को विकसित करने पर ही केन्द्रित बने रहना चाहिए। उन्हें लगता है कि अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए दिए जाने वाले समय का बेहतर इस्तेमाल गणित तथा भाषा जैसे कौशल हासिल करने और उनमें पारंगत बनने के लिए किया जा सकता है। दूसरों को लगता है कि अर्थशास्त्र का आधुनिक संसार को समझने में बहुत योगदान हो सकता है, और इसे एक नागरिक के प्रशिक्षण का अंग होना चाहिए। इसके अलावा, यह तार्किक ढंग से विचार करने के प्रशिक्षण में भी सहयोग देता है। पर, आलोचक यह भी कहते हैं कि आर्थिक प्रतिरूपों का अमूर्त स्वरूप और उनकी मान्यताओं का फिसलन भरा आधार स्कूली स्तर पर यह परिचय करवाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। दोनों ही तरफ की बातों में थोड़ी सच्चाई है। इसलिए, बहस स्कूलों के लिए अर्थशास्त्र की प्रकृति पर होना चाहिए।

उच्च–प्राथमिक स्तर

जब एकलव्य ने उच्च–प्राथमिक स्तर (अपर–प्राइमरी स्टेज–यूपीएस) के लिए पाठ्यपुस्तकें विकसित कीं तो उनमें नागरिक शास्त्र की पाठ्यचर्या के एक अंश की तरह अर्थशास्त्र शामिल था। इसे इस सोच के आधार पर शामिल किया गया था कि सभी विद्यार्थियों को प्रारम्भिक आर्थिक और सामाजिक समझ के लिए आवश्यक बुनियादी सिद्धान्तों को हासिल करने का अवसर मिलना चाहिए। अनेक ऐसे विषयसूत्र थे जो सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालने के लिए आर्थिक अध्ययनक्षेत्र से मदद ले सकते थे। परन्तु, आमराय अर्थशास्त्र को अलग से पढ़ाने के पक्ष में नहीं थी।

> *इस पर अभी भी विवाद है कि स्कूली स्तर पर अर्थशास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। अनेक लोगों को लगता है कि गणित, इतिहास या भूगोल के समान एक विशेष विषय की तरह अर्थशास्त्र पाठ्यचर्या में स्थान पाने की पात्रता नहीं रखता।*

यह समझ परीक्षणों और स्रोत–व्यक्तियों से चर्चा करने तथा उच्च–प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञानों के बारे में सही दृष्टिकोण तलाशने के प्रयासों से निकली। डॉ.पूनम बत्रा द्वारा सम्पादित पुस्तक 'सोशल साइंस लर्निंग इन स्कूल्स, पर्सपैक्टिव एण्ड चैलेंज़ेज', ऐसे कई अध्यायों को, जो कारगर नहीं हुए, दस्तावेजों की तरह देती है और इस अनुभव पर मनन करती है। इस कार्यक्रम से मिली समझ बीते वर्षों में कुछ शासकीय स्कूलों में वास्तविक अध्यापन और नियमित शिक्षक–प्रशिक्षणों के द्वारा समृद्ध बनी।

एनसीएफ 2005 ने नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम–जो पहले आई यशपाल कमेटी की रिपोर्ट (1992–1993) के अनुसार अर्थहीन विधिविधान पढ़ाने तक सिमट गया था, और जो उस समय भी लोगों को 'निष्ठावान नागरिकों' में बदलने का औपनिवेशिक ढाँचा दर्शाता था–के उद्देश्य पर बहस छेड़ी। इन विचार विमर्शों से निकली अवधारणात्मक दृष्टि इस परम्परा से अलग होने का प्रयास करती है। नागरिक शास्त्र को यूपीएस में सामाजिक और राजनैतिक जीवन (और ऊपर के स्तरों पर राजनीति विज्ञान) का नाम दिया गया है। सामाजिक और राजनैतिक जीवन के अपने नए अवतार में नागरिक शास्त्र,लिंग,संचार माध्यम और अधीनस्थ अध्ययनों तथा अर्थशास्त्र से भी अनेक प्रसंग लिए गए हैं।' सामाजिक और राजनीतिक जीवन' की पाठ्यपुस्तकों का अर्थशास्त्र वाला भाग यद्यपि छोटा है पर महत्वपूर्ण है।

कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विविध प्रकार की जीविकाओं से विद्यार्थियों का परिचय करवाया गया है। फिर कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों,स्वरोजगारी और वेतन भोगियों, औपचारिक और अनौपचारिक कामगारों के बीच अन्तर को दर्शाने के लिए और ऐसे मुद्दों, जैसे काम का अभाव, काम की भिन्न–भिन्न शर्तों और स्थितियों आदि की चर्चा करने के लिए विविध प्रकार के सन्दर्भों का अर्थपूर्ण ढंग से उपयोग किया गया है।

यूपीएस के अगले दो वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख संघटक सिद्धान्तों,बाजार और सरकार, को समसामयिक पृष्ठभूमि में समझने के लिए दिए गए हैं। विनिमय के स्थान की तरह बाजार की भौतिक धारणा (उदाहरण के लिए हाट,मण्डी, स्थानीय दुकानें,मॉल) से आरम्भ करके,बाजारों का परिच्छेद आगे इस बात की चर्चा करता है कि बाजार किस तरह एक ओर दूर–दूर के उत्पादकों और खरीदारों को जोड़ते हैं,वहीं दूसरी ओर उनके लिए व्यापक रूप से भिन्न अवसर भी पैदा करते हैं।

कक्षा 8 में सरकार की चर्चा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं–जिनको निभाने की जिम्मेदारी सरकार की मानी जाती है,जैसे सर्वशिक्षा,सार्वजनिक सुविधाएँ और आर्थिक गतिविधियों का नियमन–में सरकार की विफलता पर गौर करती है,साथ ही इस बात पर जोर देती है कि सबके लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता हासिल करने के लिए इन भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए सरकार संवैधानिक रूप से बाध्य है।

समग्र रूप से इन पाठ्यपुस्तकों में अर्थशास्त्र के खण्डों के लिए एक राजनैतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ उपयोग की गई विश्लेषणात्मक श्रेणियाँ हमेशा सरल नहीं हैं, लेकिन व्यापकीकरण करने के पहले विभिन्न प्रकार के मामलों के उपयोग, और औपचारिक विशिष्ट शब्दावली के करीब–करीब अनुपस्थित रहने से यह माना गया है कि ये प्रसंग विद्यार्थियों के लिए रोचक और समझ में आने वाले होंगे।

विषय की प्रस्तुति वास्तविक उदाहरणों और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों (परिचित से प्रारम्भ करके अधिक जटिल परिस्थितियों तक) पर केन्द्रित है। इन्हें फिर सामाजिक नैतिकता के ऐसे प्रश्नों से जोड़ा गया है जैसे 'क्या आप इसे उचित कीमत मानेंगे?' 'क्या लोगों को इस मामले में न्याय मिला?' एक अन्य दृष्टिकोण से देखें तो लोकतंत्र,बराबरी,धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के विचारों की चर्चा करने के बजाय (भारत में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम की सामान्य प्रवृत्ति) रोजमर्रा की स्थितियों में साधारण लोगों के जीवन–अनुभवों में इनके अर्थों की छानबीन की गई है।

माध्यमिक स्तर पर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए?

संयुक्त राज्य अमेरिका में महाविद्यालय से नीचे के स्कूलों में अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए वहाँ की नेशनल काउंसिल ऑन इकॉनॉमिक्स एजूकेशन अवधारणाओं का एक समूह प्रदान करती है। इसमें आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने के कौशलों को जल्दी विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाओं,जैसे अवसर की लागत, मार्जिनल (लाभांश का) विश्लेषण,विनिमय, उत्पादकता, धन,बाजार और कीमतों की सूची होती है। व्यापक अर्थशास्त्र के प्रसंगों का परिचय बाद में दिया जाता है। इस ढाँचे में आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक कार्यकुशलता को किसी अर्थव्यवस्था के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य माना गया है।

इसके विपरीत,1977 में उसकी शुरुआत से ही एनसीईआरटी द्वारा निकाली गई माध्यमिक स्तर की अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक में एक मौलिक दृष्टिकोण अपनाया गया है,जो उपरोक्त उपयोगितावादी ढाँचे से काफी भिन्न है। विकास की एक व्यापक दृष्टि, जिसका आशय केवल वृद्धि न होकर सामाजिक न्याय भी हो, अपनाते हुए अर्थव्यवस्था की संस्थानिक और संरचनात्मक रूपरेखाओं को सावधानीपूर्वक निरूपित किया गया और विकास की अवरोधक सीमाओं से उनका सम्बन्ध जोड़ा गया। रोजगार (या उसके अभाव) के मुद्दे पर पर्याप्त जोर दिया गया, और विमर्शों में बाजार के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के साथ ही सार्वजनिक नीतिगत हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अवर इकॉनोमी : एन इन्ट्रोडक्शन ने निश्चित ही भारत में हाईस्कूल अर्थशास्त्र का लहजा तय कर दिया और बाद के पाठ्यपुस्तक लेखन के सभी प्रयासों ने इस पुस्तक में प्रस्तावित समग्र रूपरेखा का ही अनुसरण किया।

पर अपनी सारी खूबियों के बावजूद, यह किताब सबसे रूढ़िवादी शैक्षणिक मानदण्डों के अनुसार भी प्रारम्भिक पाठ्यपुस्तक नहीं कही जा सकती। सभी आयुवर्गों के बच्चों को सीखने के लिए ढेर सारा अनुभव और वास्तविक स्थूल परिस्थितियों पर पूरी तरह विचार करना आवश्यक होता है,ताकि वे जीवन के उन तथ्यों तथा घटनाओं को समझ सकें जिन पर अवधारणाएँ और सिद्धान्त आधारित होते हैं। कम आयु वाले समूहों के लिए आर्थिक जीवन के स्थूल बोध की जरूरत और भी अधिक है। 'अवर इकॉनामी' में एक साथ जरूरत से कहीं ज्यादा अवधारणाएँ प्रस्तुत कर दी गईं थीं, और उनके उदाहरण और उपयोग नगण्य थे। उसकी भाषा रूखी और तकनीकी थी। इसका निहितार्थ यह था कि इस किताब को पढ़ाने वाले शिक्षक,जिनमें से अधिकांश अर्थशास्त्र के शिक्षक नहीं थे, पाठ्यसामग्री को संक्षेप करके पढ़ाएंगे और विद्यार्थी उसे परीक्षाओं के लिए याद कर लेंगे। यदि लेखक का जोर अवधारणात्मक समझ पर था, तो इससे ठीक उल्टा परिणाम हासिल हुआ।

> *इसके बजाय, अब उद्देश्य अर्थशास्त्र में अपनाए जाने वाले वैचारिक तरीकों से विद्यार्थियों को परिचित कराना है।*

इसलिए एनसीएफ 2005 (जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के नए समूह के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज था) द्वारा आवश्यक समझे गए शैक्षणिक दिशा परिवर्तन बहुप्रतीक्षित और बहुत स्वागत योग्य थे। एकलव्य सहित अनेक समूहों ने इसका अन्वेषण किया था। इसके अनुसार यह जरूरी माना गया था कि पाठ्यपुस्तकों की प्रकृति रटकर सीखने से हटकर बुनियादी बदलाव करते हुए विद्यार्थियों में अवधारणात्मक विकास और आलोचनात्मक सोच की ओर उन्मुख हो। पाठ्यपुस्तक लिखने की प्रक्रिया भी अधिक

लोकतांत्रिक हो गई थी क्योंकि पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाने, लिखने और पुनरीक्षण करने का काम एक व्यक्ति के बजाय विभिन्न दलों को सौंपा गया।

यदि हम उच्च–प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत किए गए विषयसूत्रों के साथ हाईस्कूल अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को देखें तो पाएँगे कि अवधारणात्मक भागों को विस्तार दिया गया है और कुछ औपचारिक आर्थिक उपयोगों से भी परिचय कराया गया है, ताकि विद्यार्थी इस ज्ञान को उस सबसे जोड़ सकें जो वे संचार माध्यमों में वयस्कों की बातचीत में सुनते हैं। लेकिन अमूर्तिकरण अभी भी बहुत थोड़े हैं, औपचारिक सिद्धान्त नहीं हैं और सभी विषयसूत्रों की व्यावहारिक प्रासंगिकता बरकरार है। इसका उद्देश्य सामान्य शिक्षा है। हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का एक अंग है जिसे इस विषय में इतिहास,भूगोल और राजनीति विज्ञान से साझेदारी करना है।

पहले वाली एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के उस स्तर को सीखने वालों के लिए उपयुक्त न होने का एक कारण यह था कि उस पुस्तक ने विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र का प्रमुख ज्ञान प्रदान करने की (यद्यपि मोटे तौर पर इस उद्देश्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया था) कोशिश की। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि एनसीईआरटी के हाईस्कूल अर्थशास्त्र के नए पाठ्यक्रम ने इस आकांक्षा को त्याग दिया है। इसके बजाय, अब उद्देश्य अर्थशास्त्र में अपनाए जाने वाले वैचारिक तरीकों से विद्यार्थियों को परिचित कराना है।

> *अक्सर पाठ्यपुस्तकें नई श्रेणियाँ और नई जानकारी प्रस्तुत करने पर केन्द्रित रही हैं,परन्तु अवधारणात्मक ढाँचे के भीतरी तार्किक संरचना पर जोर देने में असफल रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी की हानि हुई है। यह खासतौर से भारतीय अर्थव्यवस्था के (विभिन्न स्तरों पर) पाठ्यक्रम की खामी रही है और इसके चंगुल से बचने की जरूरत है।*

शिक्षाशास्त्री जिसे प्रसंग–आधारित पद्धति कहते हैं,उसी ढंग से पाठ्यक्रम को ऐसे विषय–प्रसंगों के इर्द–गिर्द व्यवस्थित किया गया है जो अवधारणात्मक श्रेणियों को सीखने के वास्तविक प्रसंगों को जोड़ते हैं। पहले, विद्यार्थी किसी ऐसे वास्तविक सन्दर्भ स्थिति से शुरू करता है जो उसके अपने कई अनुभवों को प्रतिबिम्बित करती है, और इसलिए किसी विशेष–प्रसंग में प्रवेश करने के लिए सुविधाजनक (और बहुत रोचक) बिन्दु प्रदान करता है। दूसरे,अवधारणात्मक क्षेत्रों को पहले से तय करने के बजाय हम आर्थिक वास्तविकता के जिस पक्ष पर विचार कर रहे हैं,उसके आधार पर अवधारणात्मक क्षेत्र निर्धारित किए जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप अर्थशास्त्र की नई पाठ्यपुस्तकों में अवधारणात्मक बोझ घट गया है और वास्तविक सन्दर्भों और स्थितियों का उपयोग बढ़ गया है।

विद्यार्थियों और शिक्षकों को व्यापक तस्वीर के साथ काम करने में कुछ प्रारम्भिक हिचकिचाहट और कठिनाई होती है,पर वे अंततः संख्याओं और लेखाचित्रों तथा आर्थिक तर्क के माध्यम से काम करना सीख ही लेते हैं। इसलिए व्यापक तस्वीर और विशिष्ट उदाहरणों के बीच सन्तुलन आवश्यक है और वह विद्यार्थियों को रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधि को अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली से जोड़ने के काबिल बनाएगा। इसे कैसे हासिल किया जाए यही बड़ी चुनौती है। बृहद दृष्टिकोण आसानी से उपलब्ध नहीं होता। उदाहरण के लिए, अनेक विद्यार्थियों और शिक्षकों को श्रमिकों की कमी के व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के आधिक्य और बेराजगारी को ही अर्थव्यवस्था के सामने 'एकमात्र' प्रमुख समस्या बताए जाने की बात स्वीकार करने में कठिनाई होती है। एक और उदाहरण लें, जहाँ बैंकों का वित्तीय बिचौलियों की तरह काम करना विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाता है,वहीं वे यह समझने में असमर्थ रहते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स भी धन का एक प्रकार होते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ बृहद दृष्टिकोण सहज ज्ञान से एकदम भिन्न हो सकता है। पाठ्यपुस्तकें रचने वालों के लिए यह एक अन्य चुनौती है।

काफी लम्बे समय से शिक्षाविद् यह मानते रहे हैं कि जो हम पढ़ाते हैं, उसके बुनियादी ढाँचे की समझ विद्यार्थियों को देना महत्वपूर्ण है। इसके पीछे क्या तर्क है और वह विभिन्न परिस्थितियों में कैसे लागू होता है? अर्थशास्त्र से एक उदाहरण दें तो ऐसी शब्दावली को समझने,जैसे क्रैडिट (उधार) और यह भी समझने कि किस प्रकार इसका अर्थ विभिन्न वर्गों के उधार लेने वालों की सामाजिक–आर्थिक हैसियत के अनुसार बदलता रहता है, का मतलब होगा एक ढाँचे को सीखना। इसे बाद के प्रशिक्षण में कई अन्य स्थितियों,जैसे कि किसानों की आत्महत्या की समस्या और ग्रामीण कर्जदारी से लेकर आपस में जुड़े बाजारों और कृषि सम्बन्धों के अध्ययन तक भी फैलाया जा सकता है।

अक्सर पाठ्यपुस्तकें नई श्रेणियाँ और नई जानकारी प्रस्तुत करने पर केन्द्रित रही हैं,परन्तु अवधारणात्मक ढाँचे के भीतरी तार्किक संरचना पर जोर देने में असफल रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप

विद्यार्थी की हानि हुई है। यह खासतौर से भारतीय अर्थव्यवस्था के (विभिन्न स्तरों पर) पाठ्यक्रम की खामी रही है और इसके चंगुल से बचने की जरूरत है। अतः हमारे सामने विश्लेषणात्मक विवरण,ढाँचे और अवधारणा बनाने की प्रक्रिया को अनुभवजन्य प्रमाणों से जोड़ने की और इसके द्वारा भारतीय आर्थिक समस्याओं को हल करने की एक सामान्य विधि प्रदान करने की चुनौती है।

सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम केप्रमुख उद्देश्य की प्रकृति उपयोगितावादी ही रही है। यह विकासात्मक मुद्दों पर अधिक जोर देता है, महत्वपूर्ण तो हैं पर आदर्शात्मक आयामों–समता,न्याय और गरिमा के मुद्दों–को समझने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह आलोचना का एक प्रमुख कारण रहा है। आर्थिक विमर्श की प्रकृति के बारे में विषय के बाहर और भीतर, दोनों ओर से काफी समय से चिन्ताएँ व्यक्त की जा रही हैं। सामाजिक नैतिकता के मुद्दों को विषय में कैसे लाया जाए? इसके लिए एक बहुविषयी दृष्टिकोण भी जरूरी है,ताकि सामाजिक विज्ञान की समग्र पाठ्यचर्या में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र में मजबूत गठजोड़ बने। इस दिशा में और काम किया जा सकता है।

पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक–प्रशिक्षण और परीक्षाओं को जोड़ना

यह मानते हुए कि कक्षा में पढ़ाने और सीखने की प्रक्रियाएँ अन्य बातों के साथ शिक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण और मूल्यांकन की अपनाई गई पद्धति पर निर्भर करती हैं, हमने दुर्भाग्य से ऐसी संस्कृति निर्मित की है जिसमें शिक्षकों के लगाव का अभाव है। अकादमिक स्तर पर शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान के वर्तमान शोध के योगदान से प्रभावित दृष्टिकोण को समझने का अधिक अवसर नहीं मिलता। इसलिए,वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित दृष्टिकोण के साथ उनके काम करने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके साथ–साथ, चूँकि मूल्यांकन का तरीका अभी भी याददाश्त पर और अध्यायों के लिए निर्धारित अंकों पर निर्भर है, अवधारणात्मक समझ का महत्व एक तरह से गौण हो गया है।

उच्चतर–माध्यमिक स्तर पर विवाद

मिडिल और सेकेण्डरी स्तर पर अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के हिस्से की तरह पढ़ाया जाता है। उच्चर माध्यमिक स्तर पर विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान हासिल करने का अवसर होता है, और इसलिए विद्यार्थियों को एक अधिक औपचारिक पाठ्यक्रम से परिचित कराए जाने की जरूरत है। लेकिन इसके बारे में किस तरह विचार किया जाना चाहिए?

हाल ही के एक विवाद में कक्षा 12 को पढ़ाने वाले अर्थशास्त्र के शिक्षकों ने सूक्ष्म और बृहद के नए प्रतिरूपों पर ऐतराज किया है, और सीबीएसई को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को स्कूलों में अधिकारिक रूप से (निर्धारित पाठ्यक्रम के भीतर) पढ़ाए जाने की अनुमति देने के लिए बाध्य किया है। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब नई पाठ्यपुस्तकों को खारिज करना हुआ। इस मामले को देख रही एक समिति ने फिर से इन किताबों को स्वीकार करने की इच्छा जाहिर की है। अकादमिक विद्वानों ने प्रतिक्रिया में कहा है कि शिक्षक मेहनत से बारीकियों पर ध्यान देने वाला दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहते। महाविद्यालयों के कुछ शिक्षकों ने टिप्पणी की है कि हम गणित की ही तरह अर्थशास्त्र के प्रति एक भय को स्थापित कर रहे हैं।

पर यह कहने के बाद, यह भी कहना होगा कि उच्चतर– माध्यमिक पाठ्यक्रम केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम– जैसा वह अभी है, जिसमें चार अलग–अलग प्रश्नपत्र हैं (सांख्यिकी,भारतीय अर्थशास्त्र, सूक्ष्म और बृहद) और इन विषयों के बीच में न के बराबर अन्तर्सम्बन्ध हैं–का सरलीकृत रूप मात्र नहीं हो सकता। इस पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की प्रेरणा क्या है? पूछने के लिए यह एक प्रासंगिक प्रश्न हो सकता है–किसी शुरुआती या युवा विद्यार्थी के लिए और भी ज्यादा। हमें विवाद का उपयोग इस मुद्दे पर रचनात्मक ढंग से काम करने के लिए एक अवसर की तरह करना चाहिए। वास्तव में ,युवा विद्यार्थियों को इसके प्रति आश्वस्त करने के लिए कि अर्थशास्त्र छोटी उम्र से पढ़ने लायक विषय है, अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

(यह लेख सुकन्या बोस एवं अरविन्द सरदाना के लेख 'टीचिंग इकोनॉमिक्स इन स्कूल्स', ईपीडब्ल्यू,अगस्त 9,2008 का संशोधित एवं परिवर्द्धित रूप है।)

अरविन्द सरदाना *की पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र की है। वे 1986 से एकलव्य में सामाजिक विज्ञान में नए पाठ्यक्रम के विकास पर काम कर रहे हैं। वे पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित करने में विभिन्न शासकीय और अशासकीय संगठनों से सम्बद्ध रहे हैं। साथ ही वे सामाजिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र की शिक्षा पर शोधकार्य में भी संलग्न हैं। उनसे इस anuarvindbali@gmail.com ईमेल पर सम्पर्क किया जा सकता है।*